औरतों को देने वाले सबसे बेहतरीन उपहार सम्मान है।
– अज्ञात

रोजगार का इंतजाम जरूरी

मनरेगा जैसी योजना की पहुंच इन जिलों और गांवों तक होने के बावजूद उससे इन मजदूरों का खास फायदा नहीं होना था क्योंकि ये अकुशल मजदूर नहीं हैं और इनके कौशल का क्षेत्र भी अलग–अलग है।

नवीन चंद्रा।

लॉकडाउन के मारे प्रवासी मजदूर जैसी विकट स्थितियों में अपने गांव पहुंचे हैं, उसे देखते हुए उनके लिए जल्दी कहीं आसपास ही रोजगार का इंतजाम जरूरी है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये की एक शॉर्ट टर्म मेगा जॉब स्कीम शुरू की है। स्कीम की घोषणा में थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको प्रवासी मजदूरों की क्षमता और जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये मजदूर कोरोना और लॉकडाउन से उपजे हालात की मजबूरियों के चलते घबराहट में गांव चले आए हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और करियर समेत ऐसी तमाम वजहें हैं जो उन्हें हालात सुधरते ही अपने पुराने कार्यस्थलों पर वापस लौटने को मजबूर करेंगी। शायद इसीलिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम की इस योजना में शहरों से आए मजदूरों को 125 दिन काम मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।

यह योजना देश के उन 116 जिलों तक सीमित रखी गई है, जहां शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या कम से कम 25,000 है। मनरेगा जैसी योजना की पहुंच इन जिलों और गांवों तक होने के बावजूद उससे इन मजदूरों का खास फायदा नहीं होना था क्योंकि ये अकुशल मजदूर नहीं हैं और इनके कौशल का क्षेत्र भी अलग–अलग है। राज्य सरकारों द्वारा करवाई गई स्किल मैपिंग के आधार पर हर किसी को यथासंभव उसके कौशल के अनुरूप काम मुहैया कराने वाली इस योजना के तहत इन मजदूरों को रोजगार देने के साथ ही संबंधित जिलों में कोई स्थायी निर्माण कार्य भी संपन्न किया जाएगा। योजना की उपयुक्तता की तारीफ करते हुए भी यह कहना होगा कि इसकी वास्तविक सफलता इसके इसी रूप में जमीन पर उतरने में है।

अमल की गड़बड़ियां तकरीबन सभी योजनाओं में कुछ न कुछ होती ही हैं, लेकिन जरूरतमंद तबकों को सहायता पहुंचाने के मकसद से शुरू हुई योजनाओं के साथ सहायक गतिविधियों की फंडिंग का सवाल तीखा हो जाता है। जैसे, योजना अगर लोगों से मजदूरी करवा कर उन्हें कुछ राहत देने की है तो अपने श्रम से जिस सड़क, पुलिया या इमारत को बनाने का काम वे संपन्न करेंगे, उसके लिए औजार उपलब्ध कराने और आवश्यक ईंट, सीमेंट, बालू वगैरह मंगवाने के लिए पैसा कहां से आएगा।

स्वाभाविक रूप से यह पैसा योजना के लिए स्वीकृत धन से ही लिया जाता है। इसमें खतरा नाक से ज्यादा अहमियत नथ को मिल जाने का होता है। यानी मजदूरी पर जितनी राशि खर्च होती है, उससे ज्यादा बाकी मदों के नाम पर निकल जाती है। नतीजा यह कि योजना की धूम भले मच जाए लेकिन जिसके लिए यह सारी कवायद होती है, उसकी हालत ऊंट के मुंह में जीरे का छौंकन पड़ने जैसी होकर रह जाती है। बहरहाल, गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर अमल से पहले योजनाकारों ने इस पक्ष पर विचार कर ही लिया होगा, लिहाजा उम्मीद करें कि योजना का अधिकतम लाभ जरूरतमंद तबके तक पहुंचेगा और इसके साथ ही इन 116 जिलों में कुछ असेट भी खड़े होंगे।

भारत में योग

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। भारत में योग की परंपरा 5000 हजार साल पुरानी है। 11 दिसम्बर 2014 को इसका प्रस्ताव दिया था। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के 177 देशों ने भारत के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद भारत दुनिया का विश्वगुरु बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 90 दिनों के भीतर पीएम मोदी के प्रस्ताव को मंजूर किया। हम योग के 21 आसनों को अपनाकर अपनी जिंदगी को सुखी, शांत और निरोगी बनाकर खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जब हम तन और मन से स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र निर्माण और उसके विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। योगगुरु बाबा रामदेव योग को वैश्विक मान्यता मिलने पर इसे भारत की जीत बताया था। दुनिया योग को अपने जीवन की दिनचर्या बना लिया है। योग संपूर्ण जीवन और चिकित्सा पद्धिति बन गया है।

संपादकीय

छोड़नी होगी दुविधा

सवाल उठता है कि भारत की मजबूरी क्या है जो वह व्यापारिक घाटा भी उठाए और चीन के विस्तारवाद को भी बर्दाश्त करे। निश्चित तौर पर भारत के लिए भूमंडलीकरण और अपने रक्षा हितों में से किसी एक को चुनने की नौबत आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता की नीति घोषित की है, लेकिन सरकार की दुविधा साफ दिखाई दे रही है। विदेशी पूंजी लगाने के लिए तरह–तरह की छूट की घोषणा लगातार हो रही है। ऐसे में यह साफ–साफ समझना होगा कि आत्मनिर्भरता और भूमंडलीकरण दोनों साथ–साथ नहीं चल सकते। चीन के मामले में तो बिल्कुल नहीं क्योंकि यहां भूमंडलीकरण और भारतीय राष्ट्रवाद में सीधा टकराव है। गौर से देखें तो साफ हो जाता है कि भूमंडलीकरण से मिली आर्थिक ताकत ने चीन के अलावा भी कई अमीर मुल्कों के राष्ट्रवाद को इसी तरह उग्र बनाया है। यूरोप और अमेरिका में भी उग्र राष्ट्रवाद की एक लहर दिखाई दे रही है। लोग अपने दरवाजे बाहर के कारोबारियों और मजदूरों के लिए बंद करने की बात कर रहे हैं। कोरोना के हमले के साथ यह प्रवृत्ति और तेज हो गई है। भूमंडलीकरण से अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ने की उम्मीद गलत साबित हुई। इसे हम कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की कोशिशों को मिली विफलता के रूप में देख सकते हैं। क्या भूमंडलीकरण से मिली ताकत का इस्तेमाल उग्र राष्ट्रवाद के लिए करना संभव है? चीन और भारत के संघर्ष में यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह संभव नहीं है। दोनो देशों के आर्थिक संबंध चीन के हित में हैं और इस पर किसी तरह की रोक लगने से उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस व्यापार के रुकने से भारत में सामानों की सप्लाई पर तो असर होगा लेकिन उसका व्यापार घाटा कम होगा।

दोस्ती की कसम खाने वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोई बातचीत तक नहीं कर पा रहे। इस घटना ने भारतीयों को वैसा ही सदमा पहुंचाया है जैसा 1962 के चीनी हमले ने पहुंचाया था।

नफा-नुकसान से ऊपर

अनिल सिन्हा।

चीन के साथ भारत के बढ़े हुए व्यापारिक संबंधों को देख कर शायद ही कोई सोच सकता था कि सीमा पर दोनों देश इस तरह भिड़ जाएंगे। व्यापार ने दोनों देशों को इतना नजदीक ला दिया था कि एक–दूसरे से खिंचे–खिंचे रहने वाले दोनों देशों के राजनयिक एक–दूसरे का स्वागत गहरे मित्रों की तरह करने लगे थे। फिर भी दृश्य बदलने में देर नही लगी। दोस्ती की कसम खाने वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोई बातचीत तक नहीं कर पा रहे। इस घटना ने भारतीयों को वैसा ही सदमा पहुंचाया है जैसा 1962 के चीनी हमले ने पहुंचाया था।

भारत के लोग यह मानने लगे थे कि चीन हमसे लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि उसे काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। चीन के साथ भारत का कारोबार वित्त वर्ष 2018–19 में 87.07 अरब डॉलर का था जो अमेरिका के साथ उसी साल हुए 87.95 अरब डॉलर के कारोबार से थोड़ा ही कम है। लेकिन यह कारोबार घाटे का है। हम उससे ज्यादा सामान खरीदते हैं और उसे बहुत कम बेचते हैं। व्यापार में चीन ने हमसे पिछले साल भी 53 अरब डॉलर का फायदा उठाया। लेकिन इतने बड़े फायदे के बाद भी भारत के

साथ पंगा लेने में वह नहीं हिचकिचाया। इसमें दुनिया के स्तर पर राष्ट्रवाद और भूमंडलीकरण के बीच का टकराव जाहिर होता है। यह कल्पना गलत साबित हुई कि पूंजी एक दिन राष्ट्र की सरहदों को पार कर जाएगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों छोटे राष्ट्र की तरह काम करने लगेंगी। आर्थिक नीतियों पर कंपनियों की पकड़ जरूर बनी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ।

चीन का उग्र राष्ट्रवाद पहले से दिखाई दे रहा है। वह विश्व–बाजार में एक दैत्याकार खिलाड़ी के रूप में खड़ा है। उसे आर्थिक रूप से परास्त करने की जोर–आजमाइश भी चालू है। अभी हाल तक कुछ लोगों को यह संभावना दिखाई दे रही थी कि कारोबार का दायरा बढ़ने के साथ ही चीन में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति सुधर जाएगी। कई लोग यह भी मानते थे कि चीन में आर्थिक सुधारों के चरम पर पहुंच जाने के बाद लोकतांत्रिक सुधारों का दौर आएगा। लेकिन चीन ने इसके कोई लक्षण नहीं दिखाए। हांगकांग के लोकतंत्र–समर्थक आंदोलन को लेकर उसका रवैया सख्त से सख्त होता गया। उदार आर्थिक नीतियों के दौर में भी उसने तिब्बती या शिनच्यांग के उइगर मुसलमानों की अस्मिता कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के बाद रक्षा–बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला वह दूसरा ताकतवर देश भी बन गया। पिछले साल उसने रक्षा पर 177.5 अरब डॉलर खर्च किया है। इस साल वह उससे भी ज्यादा खर्च कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की कीमतों को ध्यान में रखने पर यह अमेरिकी प्रतिरक्षा खर्च का 75 प्रतिशत है। मगर बात सिर्फ चीन की नहीं है। वैसे भी दुनिया में भूमंडलीकरण के दौर में हथियारों पर होने वाले खर्च में कोई कमी नहीं आई है।

इस मामले में भारत जैसे गरीब मुल्कों ने जरूर कुछ अलग किया। यहां भूमंडलीकरण की ताकतों ने राष्ट्रवाद की सीमा तोड़ने की कोशिश की। खेलों को राष्ट्रवाद के प्रदर्शन का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक और विश्व शांति के समर्थक बर्ट्रेंड रसेल ने तो युद्ध के विकल्प के रूप में फुटबॉल मैच कराने की बात कही थी ताकि लोग खेल के मैदान में अपनी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रदर्शन कर सकें।

अष्टयोग-5094

		7	1			5
3	29	6	37	2	31	1
	2		7	5		
5	30		30		31	6
		5	4		3	
2	33	4	31	3	30	7
6			5	7		

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5093 का हल

7	5	1	3	6	4	2
6	35	6	30	1	32	7
4	1	5	6	2	7	3
1	26	2	34	4	31	5
2	4	7	5	3	6	1
3	29	4	40	5	34	6
5	1	3	6	7	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

आर्थिक और सामरिक शक्ति

मोहन। भारत ने क्रिकेट को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकालने के लिए आईपीएल जैसे प्रयोग किए हैं जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दायरे तोड़कर खिलाड़ी लिए जाते हैं। चीन की ओर से ऐसी कोई कोशिश दिखाई नहीं देती। वह आईटी के क्षेत्र में दुनिया की उन बड़ी कंपनियों से होड़ ले रहा है जो सोशल मीडिया या अन्य क्षेत्रों को लोकतांत्रिक बनाने में काफी हद तक मदद करती हैं। लेकिन इस टेक्नॉलजी को वह अपने मुल्क में लोकतंत्र लाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे रहा है। यानी भूमंडलीकरण की ताकत से वह आर्थिक और सामरिक शक्ति हासिल कर रहा है लेकिन पूंजी के खुले प्रसार को अपने उग्र राष्ट्रवाद तथा निरंकुश शासन पर उसने कोई असर नहीं डालने दिया है।